



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 95-2022/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, MAY 27, 2022 (JYAISTHA 6, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 27 मई, 2022

संख्या पी०एफ०-16-बी/2022/14527.— हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन नियम, 1976, को आगे संशोधित करने के लिए नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (1975 का 8) की धारा 24 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करते हैं तथा उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित ऐसे व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित करते हैं, जिनके इससे प्रभावित होने की सम्भावना है।

नियम

1. ये नियम हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (तृतीय संशोधन) नियम, 2022, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन नियम, 1976 में, नियम 30 के उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किये जाएंगे, अर्थात्:-

“(2) अपील से संबंधित ज्ञापन के साथ दो हजार रुपए की न्यायालय फीस संलग्न होगी।”

देवेंद्र सिंह,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

HARYANA GOVERNMENT**TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT****Notification**

The 27th May, 2022

No. PF-16(B)/2022/14527.— The following rules further to amend the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Rules, 1976, which the Governor of Haryana proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 24 of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975 (8 of 1975) is hereby published as required under sub-section (1) of the said section, for the information of persons likely to be affected thereby.

Rules

1. These rules may be called the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Third Amendment) Rules, 2022.
2. In the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Rules, 1976, in rule 30, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(2) The memorandum of appeal shall bear a court fee stamp of two thousand rupees.”

DEVENDER SINGH,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Town & Country Planning Department.